हरित ख़बर
आवाज़ हरित प्रदेश की
हेडलाइंस बिजली विभाग में बिना इंटरव्यू नौकरी पाने का बेहतरीन मौका
खोजें

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता पर उठ रहे हैं सवाल

July 2, 2015

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महत्वकांक्षी का उद्देश्य देश के 2.5 लाख गाँवों को इन्टरनेट से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि इस कैम्पेन के ज़रिये एम-गवर्नेंस यानि मोबाइल गवर्नेंस से सारे सरकारी कार्य किये जाए। लेकिन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लेकर कई विशेषज्ञ कुछ वाजिब सवाल भी उठा रहे हैं। इनको इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर ही संदेह है।

- इन्टरनेट साक्षरता की है कमी, इन्टरनेट स्पीड भी है कम

भारत में इन्टरनेट साक्षरता अधिक नहीं है। एक तरफ जहाँ दक्षिण कोरिया जैसे देश में 98 लोग इन्टरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले भारत काफी पीछे है। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट में साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल कहते हैं कि भारत में लोग कम्प्यूटर और टैब से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। इससे एम-गवर्नेंस अधिक कैसे सफल हो पायेगा! साथ ही भारत में इन्टरनेट स्पीड बेहद कम है। सरकार को पहले इन समस्याओं का हल निकलना होगा।

इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक भारत इंटरनेट कनेक्टिविटी, लिट्रेसी और बैंडविड्थ जैसे मामलों में 166 देशों की लिस्ट में 129वें स्थान पर है। भारत मालदीव, मंगोलिया, केन्या, कजाख्स्तान, फिजी, निकारागुआ से भी पीछे है। देश में 20 करोड़ लोग यानी करीब 15% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। ग्रामीण भारत में केवल 9% लोग ही इन्टरनेट इस्तेमाल करते हैं।

आईटी एक्स्पर्ट अचिन जाखड़ का भी कहना है कि इन्टरनेट की स्पीड शहरों में तो ठीक-ठाक मिल भी जाती है पर गाँवों में स्थिति दयनीय है। भारत में औसत डाउनलोड स्पीड 1-2 एमबीपीएस है जो की दुनिया के तमाम बड़े इन्टरनेट इस्तेमाल करने वाले देशों से बहुत कम है। ऐसे में जो लोग ई-गवर्नेंस से जुड़ना भी चाहेंगे वे स्पीड की वजह से इससे दूर भी हो सकते हैं।

- बिना बिजली के कैसे होगा डिजिटल इंडिया

डीइआरसी के पूर्व सदस्य बीबी तिवारी का कहना है कि बगैर बिजली के डिजिटल इंडिया का सपना पूरा नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि अभी फिलहाल देश में 80 हजार मेगावॉट बिजली है, लेकिन मांग एक लाख 37 हजार मेगावाट की है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बिजली की दो-तिहाई की कमी है। यूपी में गांवों में बिजली ही नहीं आती है। लोग मोबाइल तक चार्ज नहीं कर पाते हैं तो डिजिटल इंडिया कहां से होगा।

तिवारी के अनुसार एक मेगावॉट बिजली बनाने में 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सरकार के पास बजट कहां है? उनके अनुसार एक मेगावॉट सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए 7-10 एकड़ की जरूरत होती है, इतनी जमीन कहां से लाएंगे?

- क्या व्यक्तिगत सूचनाओं के लिए सुरक्षित है डिजिटल लॉकर

डिजिटल लॉकर , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का अहम हिस्सा है।इस वेब सेवा के जरिये आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पैन कार्ड डिटेल्स जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। मगर बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार डिजिटल लॉकर को पुर्णतः हैकिंग फ्री मानती है? पूरी दुनिया के हैकरों के लिए सारी व्यक्तिगत जानकारी एक जगह पर पाने का इससे अच्छा अवसर कहाँ मिल सकता है। निश्चित तौर पर यह एक चिंता का विषय है। सरकार को इस मामले में डिजिटल लॉकर इस्तेमाल करने वालों को और इस्तेमाल करने की इच्छा रखने वालों को विश्वास में लेना होगा।

अन्य बड़ी ख़बरें

उत्तर प्रदेश : पंचायत चुनाव की तैयारी में
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम

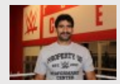
भारत की तरफ से दूसरे डब्ल्यूडब्ल्यूई
सोनीपतः देश में यूँ तो कितने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के

फेसबुक पोस्ट में सासंदों पर लिखकर फंसे
नई दिल्ली मानसून सत्र में अपने गर्म तेवरों से सरकार को

यूपी ग्राम पंचायत चुनाव: महिला प्रधान या
उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में होने वाले पंचायत चुनाव जैसे-जैसे

ये हैं भारत में खेत नापने के लिए प्रयोग
भारत के अधिकांश भागो में खेतों के नाप के लिए

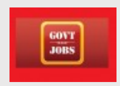

उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में लेखपाल के
लखनऊ राजस्व विभाग में लेखपाल के 12 हजार पदों पर

भारत कृषिप्रधान देश या किसानों की
सरकार ने 13 मार्च को संसद में जानकारी दी कि

चर्चा में

उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में लेखपाल के 12 हजार पदों पर भर्ती जल्द

न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
Enter your email address
GO

Tweet
Like Share 7

संबंधित ख़बरें

बिजली विभाग में बिना इंटरव्यू नौकरी पाने का

राहत भरी खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए

यूपी उपचुनाव में सपा को लगा झटका, दो सीटों पर

ताज महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ में सुनिधि और

भाजपाई देशभक्ति के दोहरे मापदंड

भारत ने दक्षिण एशियाई खेलों में लगाया पदकों का

प्रधानमंत्रीजी के नाम एक दुखियारी भैंस का खुला

अब मोबाइल फोन से क्षेत्रीय भाषा में भी भेज

यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम

गरीबों के लिए नहीं उठाए कोई कदम, अमीरों का है

यूपी में 41,610 सिपाहियों की भर्ती के परिणाम एक

विकास की दौड़ में मेरठ के हिस्से आयी गंदगी और

रिजल्ट घोषित हुआ लोअर सब-ऑर्डिनेट 2013 का,

जेएनयू शिक्षक और छात्रों की कोर्ट में पिटाई, जयंत

ऑक्सीजन मशीनें लगाई जाएंगी सभी बीएमसी में

यूपी के गाँवों में छोटे उद्योग स्थापित करने के

समाचार
राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय
कारोबार
ज़रा हटके
आपकी बात
संपादकीय

शहर
अलीगढ़
आगरा
नोएडा-गाजियाबाद
बरेली
मथुरा
मुरादाबाद
मुज़फ्फ़रनगर
मेरठ
अन्य शहर

ख़ास
फोटो गैलरी
वीडियो

बड़ी ख़बरें
> बिजली विभाग में बिना इंटरव्यू नौकरी पाने का
> राहत भरी खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए
> यूपी उपचुनाव में सपा को लगा झटका, दो सीटों पर
> ताज महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ में सुनिधि और श्रेया
> भाजपाई देशभक्ति के दोहरे मापदंड
> भारत ने दक्षिण एशियाई खेलों में लगाया पदकों का

संपर्क करें
0124 4013378
contact@haritkhabar.com
H- 16/6, DLF सिटी -1, सिकंदरपुर, गुड़गाँव
हमारे बारे में

Copyright 2015 © Harit Khabar
Created by Eyebridge